मैनुअल–4

नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जन प्रतिनिधि से परामर्श के लिए बनायी गयी व्यवस्था का विवरण

नीति निर्धारण हेतु

5.1 ग्रामीण विकास विभाग द्वारा नीति निर्धारण के संबंध में जनता या जन प्रतिनिधि को परामर्श/भागीदारी का प्रावधान :–

क्र० सं०	विषय/कृत्य का नाम	क्या इस विषय में जनता की भागीदारी अनिवार्य है? (हाँ/नहीं)	जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए की गयी व्यवस्था
1.	केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का चयन तथा भावी योजनाओं का अनुमोदन	हाँ	त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्था के माध्यम से व्यवस्था लागू कराने का प्रावधान है

5.2 ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जन प्रतिनिधि के भागीदारी का प्रावधान :–

क्र० सं०	विषय/कृत्य का नाम	क्या इस विषय में जनता की भागीदारी अनिवार्य है? (हाँ/नहीं)	जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए की गयी व्यवस्था
1.	1. इन्दिरा आवास योजना 2. राष्टीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, बिहार 3. आई.डब्लू.डी.पी. 4. डी.पी.ए.पी.	हाँ	1. संशोधित बी०पी०एल० सूची के आधार पर ग्राम सभा का अनुमोदन । 2. ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद् के माध्यम से योजनाओं का कार्यान्वयन। 3. तदैव 4. तदैव